377 279

should have become bogged down in petty intrigues and administrative bungling. I would urge that the Government of India should immediately move to take over Aurobille as a national memorial of Sri Aurobindo and for this purpose bring a Bill before the Parliament as early as possible.

(iv) SUPPLY OF ESSENTIAL COMMODITIES AT REASONABLE PRICES.

श्री हरिकंश बहादुर (गोरखपुर) : उपाध्यक्षः महोदय, इस समय सभी ग्रावश्यक वस्तुग्रों की कीमतें तेजी के साथ बढ़ती जा रही हैं । चीनी, दाल, तेल, साबुन एवं भ्रन्य भ्रावश्यक उपभोक्ता वस्तुग्रों के मूल्य में पुन वृद्धि हो गयी है । चीनी का दाम कहीं-कहीं तो ग्राट रूपए प्रति किलो हो गया है, जिससे गरीब भ्रादमी तो उस खरीद भी नही सकता । गृह की भी कीमत एक माह के भीतर दुगुनी हो गयी है । बेबी फड़ की कीमत प्रायः बढ़ती चली जा रही है । मरकार की वतमान ग्राध्यक नीति में निहत होष के कारण बढ़ती हुई कीमतों पर नियंत्रण नहीं स्थापित हो पा रहा है । बहुत सी वस्तुयें जस सीमेंट ग्रादि तो उपभोक्ताग्रो को मिल भी नहीं पा रही है ।

श्रनः सरकार को शीघ्र प्रभावशाली कदम उठाने चाहियें जिससे उपभोक्ता वस्तुये सस्ते दामों पर ग्रासानी से लोगों को उपलब्ध हो मकें। बजट पेश होने के बाद उपभोक्ता वस्तुग्रों के म्ल्यों में बेतहाशा वृद्धि ग्रत्यन्त चिन्ताजनक है। नागरिक ग्रापूर्ति मंत्रालय को तत्काल इस दिशा में प्रभावी कार्यवाहो करनी चाहिए।

(v) NEED TO RESUME RELIEF WORK IN THE TRIBAL AREAS OF JHABUA RAT-ALM, DHAR AND KHARGON DISTRICTS MADHYA PRADESH.

श्री विलीप सिंह भूरिया (झाबुग्रा): उपाध्यक्ष महोदय, मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में झाबुग्रा रतनाम, धार, खरगीन जिलों के ग्रादिवासी के लों में जहां एक भीर ग्रकाल राहत कार्य बन्द कर दिए गए हैं, वहां दूसरी भ्रोर कई महीनों की मजदूरी का भुगतान उन्हें नहीं किया गया है। साथ ही सस्ते भ्रनाज की दुकानों में भ्रादिवासियों का मध्य भोजन मोटा भ्रनाज, ज्वार, मक्का ग्रादि उपलब्ध नहीं हैं। बाजार में उने दामों में भ्रनाज मिल रहा है, जिस भ्रादिवासी श्रय नहीं कर सकता है।

भ्रतः सर्वक्ष भ्रादिवासियों में भूखमरी एवं ग्रसन्तोप व्याप्त है । राज्य सरकार को निर्देश दये जाये कि जब तक नई फसल नहीं पके तब तक राहत कार्य जारी रखे जारें एवं मजदूरी का अविलम्ब भुगतान किया जाये और शासकीय सस्ते अनाज की दुकामों पर मोटे अनाज की ध्यवस्था की जाये ।

(vi) NEED FOR IMMEDIATE SUPPLY OF WHEAT FOR "FOOD FOR WORK" PROGRAME IN RAJASTHAN.

भी बृद्धि चन्त्र जैन (बाडमेर): उपाध्यक्ष महोदय, भारतीय खाद्य निगम ने राजस्थान प्रान्त में गेहूं का स्टाक जो उनके गोदामों में जमा कर रखा था, उक्त स्टाक प्रान्त में दस दिन से बिल्कुल समाप्त हो गया है । जिसके कारण राजस्थान प्रान्त में जिला बाडमेर, जैसलमेर, भादि में ग्रकाल राहत कार्य चलते थे, वह बन्द हो गए हैं। ग्रन्य कार्य जो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के भ्रन्तर्गत चल रहे थे दे सभी बन्द हो गए हैं सस्ते अनाज की दुकानों में प्रान्त भर में गैहुं के न मिलने के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में भयंकर ग्रसन्तोष् है। गेहं के भाव चरम सीमा पर पहुंच गए हैं। ग्रकोल राहत कार्य एकं भ्रताज के बदले कार्य, फृष्ड फार वर्क नहीं चलने से कुछ जिलों में भुखमरी की स्थिति भ्रा रही है। भ्रतः केन्द्र सरकार तुरन्त राजस्थान प्रान्त में गेह का स्टाक जल्दी से जल्दी पहुंचा कर राजस्थान की जनता की भावश्यक मांग की पूर्ति करे।

(vii) REPORTED VIOLATION OF THE COM-PANIES ACT, INDUSTRIAL DEVELOP-MENT AND REGULATION) ACT, FOREIGN EXCHANGE REGULATION ACT, ETC., BY FOREIGN COMPANIES OPERATING IN INDIA.

SHRI JYOTIRMOY BOSU (Diamond Harbour): Mr. Deputy-Speaker, Sir, it has been reported that official inspection has brought out that branches and subsidiaries of Foreign Companies operating in India are violating with impunity the Companies Act, Industrial Development Regulation Act (Licencing), Foreign Exchange Regulation Act and MRTP.

The British companies numbering 319 some time ago were on top of the list in this adventure. Although the number has come down because of FERA compulsion, they have increased the remittances considerably. Their assets are soing up by leans and bounds. In 1973-74, the white money value of their assets was